कि देश में खाद्य तेलों की मांग व आपूर्ति के बीच अन्तर है। इसके लिए कुछ कारण आबादी में वृद्धि होने की वजह में वृद्धि होना तथा लोगों का बढ़ता हुआ जीवन स्तर है। कृषि मंत्रालय के अनुसार देश में खाद्य तेलों की मांग को पूरा करने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक खाद्य तिलहनों की 230 लाख मी० टन मात्रा का उत्पादन करना अपेक्षित है।

उत्तर प्रदेश में गोदामों और भाण्डागारों की कमी

803. **प्रो० राम बख्श सिंह वर्मा : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनकि वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं के भंडारण के लिए उत्तर प्रदेश में पर्याप्त गोदाम और भांडागार उपलब्ध नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो भंडागारों और गोदामों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : उत्तर प्रदेश सरकार से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नही हुई है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार, संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले क्षेत्रों में गोदामो का निर्माण करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता देती है ।

दिल्ली में गोदामों की कमी

804. **प्रो० राम बख्श सिंह वर्मा : क्या नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में नागरिक आपूर्ति विभाग के गोदामों की भारी कमी है और गोदामों के दूर-दूर होने के कारण विभाग को परिवहन का ज्यादा खर्च उठाना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली सरकार ने नए गोदाम बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दिल्ली सरकार ने साहिबाबाद और लोनी में गोदामों के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं। दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के पास दिल्ली में केवल तीन गोदाम हैं । तथापि, खाद्यान्न क्योंकि सार्वजनकि वितरण प्रणाली के तहत वितरित की जाने वाली वस्तुओं का एक बड़ा भाग होते है। अतः इन्हे दिल्ली की उचित दर दुकानों को भारतीय खाद्य निगम, जिसके दिल्ली मे छः गोदाम है, के गोदामों से जारी किया जाता है । यह कहना सही नही होगा कि दिल्ली में गोदामो की भारी कमी है । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने गोदामो की अवस्थिति के कारण उच्च ढुलाई लागत की कोई घटना सूचित नही की है ।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने संपुष्ट सार्वजनकि वितरण प्रणाली के तहत लाये गए क्षेत्रों में गोदामों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता मुहैय कराने के लिए केंद्रीय सरकार की योजना स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता की मांग की थी ।